



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

24/11/72

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 585]

नई दिल्ली, सोमवार नवम्बर 29, 1971/अग्रहायण 8, 1893

No. 585]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 1971/AGRAHAYANA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November 1971

S.O. 5253.—Whereas the Central Government and the Metal Corporation of India have failed to reach an agreement regarding the amount of Compensation as required to be paid to the said company under section 10 of the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966 (36 of 1966);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of Shri J. R. Mudholkar, a former Judge of the Supreme Court, to determine the amount of compensation payable to the Metal Corporation of India for the acquisition of its undertaking under the said Act.

The Tribunal is expected to submit its report as soon as possible and in any event within a period of eight months from the date of this notification

The Headquarters of the Tribunal shall be at New Delhi.

[No. F. 7(1)Met.II/71.]

T. N. LAKSHMINARAYANAN, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1971

एस० ओ० 5253 —यतः मेटल कार्पोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1966 (1966 का 36) की धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार और मेटल कार्पोरेशन आफ इंडिया उक्त कम्पनी को यथा अपेक्षित संदाय किए जाने वाले प्रतिकर की राशि की बाबत करार पाने में असफल हो गए हैं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा II की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन मेटल कार्पोरेशन आफ इंडिया को उसके उपक्रम के अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की राशि को अवधारित करने के लिए आ० आर० म. धोलकर, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश को समाविष्ट करके एक अधिकरण एतद्वारा गठित करती है ।

अधिकरण से आशा की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में इस अधिसूचना की तारीख से आठ मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

[सं० फा० 7(1)/धातु II/71]

टी० एन० लक्ष्मीनारायण, संयुक्त सचिव ।